ग्रामीण अर्थतन्त्र के वित्तीय समावेशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान

* डॉ. सुरेन्द्र यादव

सार

ग्रामीण अर्थतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। यह अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदैव एक संतुलक की भूमिका अदा करता रहा है। 90 के दशक के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से उदारीकरण हुआ उस उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ कदमताल करने में ग्रामीण क्षेत्र कहीं पिछडते चले गये। शहरी क्षेत्र जहॉ तेजी से वित्तीय समावेश का लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ रहा था वहीं ग्रामीण क्षेत्र अभी भी 60 और 80 के दशक में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ मिलने की उम्मीद संजोए बैठा था। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायकता की कम सम्भावना और अपेक्षाकृत लघु पैमाने की आर्थिक गतिविधियों ने यहां विकास के प्रवाह को और भी सीमित कर दिया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में वित्तीय समावेश ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए अपरिहार्य हो जाता है और इस ग्रामीण वित्तीय समावेश की प्रक्रिया को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करते हुए सुगमता से और शीघ्रता पूर्वककिया जा सकना सम्भव हुआ है।

अध्ययन का उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली की लाभदायकता का मुल्यॉकन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली के विस्तार के लिए उठाए जा सकने वाले सम्भावित कदमों की पहचान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन पद्धतियों को पहचानना जिसकी मदद से बैंकिंग प्रणाली का सुदृढीकरण किया जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति के अनुरूप प्रौद्योगिकी में किए जा सकने वाले बदलावों की पहचान करना।

परिचय

ग्रामीण अर्थतन्त्र को समझने के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण का अर्थ समझना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र अथवा ग्राम एक सामुदायिक इकाई है जहॉ एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हैं जो अपनी

आजीविका के प्राथमिक श्रोत के रूप में कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। भारत के जनगणना विभाग ने शहरों को तो परिभाषित किया है परन्तु वे ग्रामों को परिभाषित नहीं करते हैं । जनगणना विभाग की शहरों की परिभाषा के आधार पर यदि ग्रामों की परिभाषा का निर्माण किया जाये तो ग्रामों को ऐसे मानवीय अधिवासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहॉ पॉच हजार से कम जनसंख्या हो जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि हो साथ ही जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति से कम हो। अतः ऐसे समस्त क्रियाकलाप जो ग्रामीण मानवीय समुदाय की आजिवीका के निर्वहन के लिए संपादित किये जाते हैं सम्मिलित रूप में ग्रामीण अर्थतन्त्र का निर्माण करती हैं।

वित्तीय समावेश की प्रक्रिया के तीन आयाम हैं –

- समाज के पिछड़े एवं कम आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- वित्तीय सेवाएं वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हों।
- उचित एवं पारदर्शी ढंग से सेवाऍ उपलब्ध हों।

UNO के अनुसार सभी परिवारों के लिए बचत या जमा सेवाओं , भुगतान और स्थानान्तरण सेवाओं, क्रेडिट और बीमा सेवाओं सहित वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला उचित लागत पर पहुचे यही वित्तीय समावेशन है।

स्वतन्त्रता के समय ग्रामीण साख का 93 प्रतिशत गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। संगठित बैंकिंग सेवाऍ लगभग अनुपस्थित थी। भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थतन्त्र में साख पूर्ति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया इसी का परिणाम था की भारत सरकार के द्वारा 1969, 1980 में दो चरणों में 20 बैकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकी ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग ढंचे का विकास हो सके साथ ही 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की और 1982 में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक की स्थापना की गयी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर ग्रामीण साख सर्वे

समीतियों की स्थापना कर ग्रामीण साख की स्थिती का मुल्यॉकन किया परन्तु इन सभी के सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

- उच्च परिचालन लागतें
- निम्न साख जमा अनुपात
- बैंकों द्वारा अपर्याप्त प्रयास
- मानवसंसाधन की ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को लेकर अनइच्छुकता
- आवश्यक आधार ढॉचे का अविकसित स्वरूप
- ऋणयोग्य कोषों की अपर्याप्तता
- वित्तीय शिक्षण का अभाव

ग्रामीण अर्थतन्त्र के वित्तीय समावेशन हेतु किये गये समस्त राजनीतिक, आर्थिक प्रयासों के विफल हो जाने के उपरान्त एक मात्र प्रकाश पुॅन्ज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी के अनुप्रयोग के माध्यम से सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के मध्य उत्पन्न हो चुकी दूरी को पाटना सम्भव होगा।

वित्तीय समावेशन के मार्ग में आ रही उपरोक्त सभी कठिनाईयों को बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने आश्चर्य जनक रूप से दूर करने में सहयोग प्रदान किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने इस क्षेत्र में दो प्रमुख कार्य किये हैं–

1 इसके अनुप्रयोग ने हस्तानान्तरण अथवा सम्प्रेषण लागत में प्रभावी कमी की है जिससे बैंकिंग उत्पादों तक निर्धनों की पहुॅच सुगम हो सकी है।

2 इसके अनुप्रयोग ने साख क्षमता प्रोफाइल का निर्माण किया है जो अन्ततः निर्धनों की ऋण

उत्पादों तक पहुँच सुगम बनाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ही Automated teller machines, Cash Deposit Machines, cheque Deposit Machines, Cheque Scan and transfer Machines, Passbook Printing Machines, internet and mobile banking, Payment Wallets जैसी क्रान्तीकारी संरचना बैंकिंग ढॉचे को उपलब्ध करायी है जिसके कारण बैंकिंग सुविधाओं का विकास एवं विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सहजता से किया जा रहा है

तीव्र सम्प्रेषण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Electronic Data Interchange (EDI), Society for Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication (SWIFT), Core Banking Solutions (CBS) जैसी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं का सृजन किया है।

उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ही Biometric पहचान प्रणाली को विकसित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन के लिए भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित की गई एक ऐसी अवधारणा है जो उपभोक्ताओं से 95000 रू. तक की जमाएं स्वीकार करते हैं इस सीमा को भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। ये बैंकिंग संस्थाएं उपभोक्ताओं के बचत एवं चालु दोनों ही प्रकार के खाते खोल सकती हैं साथ ही ये ए.टी.एम., डेबिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर सकती हैं। भुगतान बैंकों ने बैंकिंग के क्रियात्मक स्वरूप को सरलीकृत करने का कार्य किया है वर्तमान में भुगतान बैंकों का 81 प्रतिशत व्यवसाय इन्टरनेट आधारित मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संचालित हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बैकिंग की एक नवीन अवधारणा Micro Banking को जन्म दिया है जो सभी प्रकार की बैकिंग सुविधाओं को निर्धनतम व्यक्ति

के द्वार तक पहुॅचाने का कार्य करती है।

वित्तीय समावेशन का एक महत्वपुर्ण आयाम सरकार और जन सामान्य के मध्य वित्तीय सत्प्रेषण भी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इसे भी Direct Benefits Transfer Scheme (DBT) जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से व्यवस्थित, परिणाम उन्मुखी, लक्ष्यसमुह केन्द्रित बनाने में मदद की है।

वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एक ऐसी बैकिंग संरचना को विकसित करने में सहयोग प्रदान किया है जो न केवल लागतों में प्रभावी कमी करती है अपीतु उसकी पहुॅच जन सामान्य तक सुनिश्चिम करती है।

*** सहायक आचार्य, ई. ए. एफ. एम.,**
राजकीय महाविद्यालय, करौली

सन्दर्भ सूची

1. Bubna, A., and B. Chowdhry. 2010. “Franchising Microfinance.” Review of Finance 14 (3): 451–476. [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
2. Buchenau, J., and R. L. Meyer 2007. “Introducing Rural Finance into an Urban Microfinance Institution: The Example of Banco ProCredit El Salvador.” In International Conference on Rural Finance Research: Moving Research Results into Policies and Practice, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, March 19–21. [Google Scholar]
3. Kochar, A. 1997. “An Empirical Investigation of Rationing Constraints in Rural Credit Markets in India.” Journal of Development Economics 53 (2): 339–371. [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
4. Sanjeev Kumar Gupta, (2011), Financial inclusion-IT as enabler, RBI occasional paper, Vol. 32, No.2 Retrieved from: rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/OCFI261012_SN2.pd
5. Government of India, Planning Commission, (2009), A Hundred small steps, Sage publication. Retrieved from: planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_fr/cont_fr.pdf.

6. Amol Agrawal, (2008), The need for financial inclusion with an Indian perspective, Committee on Financial Inclusion, IDBI Gilts Ltd. Retrieved from: http://ftp.solutionexchange.net.in/public/mf/comm_update/res-15-070408-20.pdf.
7. Ministry of Finance, (2012), Banking, Insurance, Pension, A journal of the department of financial services, Issue1. Retrieved from:http://financialservices.gov.in/DFS% 20 Journal %20(F).pdf.
8. Indian Banks Association, Indian Banks Association, IT-enabled Financial Inclusion, Dept of Social Banking. Retrieved from: http://www.iba.org.in/events/ITEnabled%20FinInclApproachPaper.pdf.
9. Dr. K. C. Chakrabarty, (2013), Revving up the Growth Engine through Financial Inclusion, 32nd SKOCH Summit, Retrieved from: http://rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView .aspx?Id=813.
10. V. Leeladhar, (2006), Taking Banking Services to the Common Man - Financial Inclusion, Reserve Bank of India Bulletin. Retrieved from: http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/68236.pdf.
11. RBI, (2008), Financial Literacy and credit counselling centres, Retrieved from: http://www.rbi.org.in/scripts/publicationdraftreports.aspx?id=526.